जन गर्जन

वर्ष 23 अंक 10 मासिक नई दिल्ली जून 2009 विक्रमी संवत्-2066 प्रधान संपादकः देवब्रत बिश्वास, वार्षिक-शुल्कः 60रुपये

समझौतावाद विरोधी सम्मलेन की भावना जाग्रत करें

देवब्रत बिश्वास, महासचिव, अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक

आज से करीब 70 साल पहले 19 मार्च 1940 को महान क्रांतिकारी नेता देशभक्त नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने रामगढ़ में आयोजित समझौता विरोधी सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इस सम्मेलन के माध्यम से देश को 'साम्राज्यवाद के खिलाफ समझौताहीन संघर्ष' का आह्वान किया था।

अगर हम आजादी पूर्व के द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान (1939-40) के संघर्षमय दिनों की तुलना आज (2009-10) से करने बैठे तो सप्रमाण पाते हैं कि आज की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकत अमेरिका की वर्चस्व वाली दुनिया में केचन अपनी आजादी को छोड़कर तब से स्थितियों में कोई भिन्नता नहीं है। हमारा देश एक बार फिर उसी तरह साम्राज्यवाद का शिकार होने के कगार पर है जैसा उस समय हुआ था। इसलिए, आज के समय में एक बार फिर यह प्रासंगिक हो गया है कि हम 1940 में रामगढ़ में हुए समझौतावाद विरोधी सम्मेलन की भावना को जाग्रत करें, भले ही सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों और रणनीति में कुछ बदलाव आ गया हो या करना पड़े।

1939-40 के दौरान मूल प्रश्न यह था कि हम कैसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष करें और अपनी आजादी को प्राप्त करें। 2009-10 में प्रश्न यह है कि कैसे हम केंद्र की कांग्रेस नीत सरकार की उन नीतियों के खिलाफ संघर्ष करें, जिन नीतियों के कारण हमारा देश आज की दुनिया में साम्राज्यवादी-पूंजीवादी ताकतों का सबसे बड़ा नेता अमेरिका का रणनीतिक साझीदार बनने जा रहा है। यह रणनीतिक साझेदारी हमारी संप्रभुता को तो प्रभावित करेगी ही, हमारी स्वतंत्र विदेश नीति को पूरी तरह चौपट कर देनेवाली है। साम्राज्यवादी वैश्विकरण और निजीकरण की नीतियां हमारी आर्थिक नीतियों को भी संपन्न वर्गों के हित में और जनविरोधी बनानेवाली हैं। हमारी केंद्र की वर्तमान कांग्रेस नीत सरकार से मिलीभगत कर अमेरिका हमारी रक्षा और सुरक्षा व्यवस्था, हमारी अर्थनीति और संस्कृति, हमारी शिक्षा और हमारी पूरी जीवन शैली पर अपना प्रभाव जमाना चाहता हैं।

इस प्रकार हम अमेरिका नीत विपरीत और खतरनाक स्थितियों की ओर बढ़ रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम इस तरह की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ें। स्पष्ट तौर पर यह लड़ाई वाम और प्रगतिशील ताकतों की एकता के आधार पर ही लड़ी जा सकती है। साम्राज्यवाद के खिलाफ हमारी अंतिम जीत के लिए और वामपंथ की जीत के लिए हमें सुभाष चन्द्र बोस रामगढ़ में किए गए समझौता विहीन संघर्ष के आहृवान की भावना को पुनर्जाग्रत करना होगा। सुभाष ने सही ही कहा था, 'आदमी ज्ञान की खोज में लगा रहता है और जैसे-जैसे उसका अनुभव बढ़ता जाता है, वह महसूस करता है कि यह तथ्य पूरी तरह सत्य है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है।'

खुद सुभाष ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था, 'रामगढ़ सम्मेलन देश की साम्राज्यवाद से समझौता करनेवाली तमाम ताकतों से लड़ने को कमर कसे सभी साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों को प्रोत्साहित करने के प्रति प्रतिबद्ध है।' लेकिन इसी भाषण में सुभाष ने छद्म वामपंथ और अति वामपंथ के खिलाफ भी चेतावनी दी थी, जो साम्राज्यवाद से लड़ाई में हमारी कोई मदद नहीं करनेवाले होंगे। ठीक यही चेतावनी आज भी साम्राज्यवाद और इसके कांग्रेसी सहयोगियों से लड़ाई में पूरी तरह से प्रासंगिक है। सबके बावजूद कांग्रेस का दक्षिणपंथी धरा आजादी की लड़ाई के दिनों से अब तक हमेशा साम्राज्यवाद से समझौता करता आया है। सुभाष ने रामगढ़ में उचित ही कहा था, 'हमारी गतिविधियां पूरे देश के स्तर पर ऐसे राष्ट्रीय सम्मेलन में उन सब ताकतों पर केंद्रित होनी चाहिए जो साम्राज्यवाद से किसी तरह का समझौता नहीं करने वाले हैं।'

आज की भी सबसे बड़ी जरूरत यही है। और यह काम वामपंथियों को ही करना होगा। नेताजी ने भी उन्हें 1940 के शुरू में ही सलाह दी थी, 'अगर वे तमाम खतरों, परेशानियों और बाधाओं के बावजूद साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई की एक मजबूत और समझौताविहीन नीति बनाते हैं तो वामपंथी देश में नया इतिहास बना डालेंगे और पूरा भारत वामपंथ के झंडे के नीचे आ जाएगा।'

और अंत में सुभाष ने अपने कदम और अपनी भूमिका को स्पष्ट किया, जिसे वामपंथ के लिए तैयार किया था। रामगढ़ में उन्होंने कहा था, 'भारतीय वामपंथियों को भविष्य में न केवल साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष करना होगा बल्कि उन्हें इसके भारतीय सहयोगियों के खिलाफ भी पूरी शिद्दत से संघर्ष करना होगा।'

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक ने आयला पीड़ितों के लिये राहत शिविर लगाये

पश्चिम बंगाल में 25 मई 2009 को आये विनाशकारी आयला चक्रवात से राज्य के तटीय क्षेत्रों में जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया। चक्रवात से काफी संख्या में जीवन और संपत्ति का नुकसान हुआ। उत्तरी व दक्षिणी 24 परगना जिलों के सुन्दरवन क्षेत्र में काफी बड़ी संख्या में जानमाल की हानि हुयी, अमानवीय कष्टों के अलावा अभूतपूर्व क्षति हुयी। फारवर्ड ब्लॉक की बंगाल राज्य कमिटी ने तुरंत निर्णय लेते हुये अपने सचिव स्तरीय कमिटी की बैठक बुलाकर एक आपात स्थिति के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों के लिये तुरन्त राहत कार्यों की अपनी योजनाओं को तैयार किया। इस अल्प सूचना में भी उपलब्ध संसाधनों के साथ पार्टी राहत कार्यों में जुट गयी, जिसे लोगों ने बहुत सराहा। पार्टी ने राहत शिविरों का आयोजन सहयोगी वाम दलों के साथ मिलकर भी किया तथा और अपने मंत्रियों एवं मंत्रियों और विधायकों के विभिन्न निगमों के साथ भी मिलकर, जिला तथा राज्य स्तरी पार्टी कार्यकर्ताओं तथा नेताओं के साथ मिलकर भी सहयोग किया। पार्टी ने चक्रवात में फंसें लोगों को तुरन्त राहत पहुँचाने के लिये बड़ी मात्रा में राहत सामग्री और पैसे एकत्रित किये और उसे घर-घर पहुँचाने के लिये यातायात की व्यवस्था की।

संग्रह की गयी राहत सामग्रियों की छोटी सूची इस प्रकार है-

(क) पश्चिम बंगाल आवश्यक वस्तु आपूर्ति निगम : चावल (100 क्विंटल), दाल (30 क्विंटल), धोती (1000 मात्रा), लूंगी (2000 मात्रा), दूध पावडर (1.5 टन), पानी की पाउच (30,000), खाने योग्य तेल (1000 लिटर) - कुल लागत लगभग 8.5 लाख। इसके अलावा निगम ने 3 लाख का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष में भी दिया।

(ख) पश्चिम बंगाल राज्य बीज निगम : चिरा (30 क्विंटल), गुड़ (5 क्विंटल), दूध पावडर (150 किलो), पानी की बोतलें (18000), बिस्कुट (150 किलो), ओआरएस (3000 पैकेट) - कुल लागत लगभग 6.5 लाख।

इसके अलावा 5 लाख का योगदान मुख्यमंत्री राहत कोष को दिया।

(ग) पश्चिम बंगाल मार्केटिंग बोर्ड और आरएमसी मजदूर यूनियन : तारपौलिन (1100), चीरा (20 बैग + 15 बैग), गुड़ (10 बैग+250 किलो), साबुन (500 पीस), बिस्कुट (3000+3000 पैकेट), दूध पावडर (500 पैकेट), ओआरएस (500 पैकेट), पानी की बोतल (200+1800 लीटर), ब्लीचिंग पावडर (4 बैग), कुल लागत लगभग 6,42,000 रुपये)

इसके अलावा 10 लाख का योगदान मुख्यमंत्री राहत कोष को दिया।

(घ) कन्फेड : चावल (30 क्विंटल), दाल (10 क्विंटल), पानी (20 हजार बोतल), बिस्कुट (10 टिन) - कुल लागत लगभग 3,15,000 रुपये।

इसके अलावा 2 लाख का योगदान मुख्यमंत्री राहत कोष को दिया।

(ङ) अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक बंगाल राज्य कमिटी : कमिटी ने 5 लाख का योगदान वाम फ्रंट फण्ड राहत कोष को दिया।

(च) वाम फ्रंट : वाम फ्रंट ने 30 लाख का योगदान मुख्यमंत्री राहत कोष को दिया।

राष्ट्रपति के भाषण से लाखों बेरोजगार युवकों को निराशा

4 जून 2009 को लोकसभा के संयुक्त सत्र में भारत के राष्ट्रपति ने संबोधित करते हुये अपने एक घंटे के लंबे भाषण में अनेक बड़े विषयों पर संबोधित किया। ये विषय देश की प्रमुख समस्याओं और सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं और अगले पंचवर्षीय कार्यक्रमों के संदर्भ में थे। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने बाद में बताया कि उक्त भाषण सरकार की नीतिगत दस्तावेज पर आधारित थे इसलिये गंभीर चिंतन के योग्य थे। अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के दोनों के सांसदगणों ने उक्त भाषण पर अपने प्रतिक्रिया राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रस्तुत की। इस प्रस्ताव की मुख्य बातें निम्नलिखित है:

'हम भारत की जनता का अभिवादन करते है कि उन्होंने इस 15वीं लोकसभा के चयन में मतदान के द्वारा निष्पक्ष निर्णय दिया और अनेक तथाकथित विद्वानों की भविष्यवाणियों को झूठला दिया। विद्वानों की राय के विरुद्ध जनता का निर्णय उसकी निराशा और महत्वकांक्षा पूरी न होना दर्शाता है जिसे ये विद्वान महसूस नहीं कर सके। वास्तव में वाम मोर्चे ने इस चुनाव में काफी नुकसान उठाया है। पूरी विनम्रता के साथ हम जनता के निर्णयों का स्वागत

करते हैं और आत्मनिरीक्षण के लिये बाध्य होते है। हमलोग पहले से ही चिंतन की इस प्रक्रिया में लगे हुये है और जनता के विश्वास को शीघ्र प्राप्त करने की आशा रखते हैं।

गरीब और आम आदमी की पीड़ा बनी हुयी है, यह प्रमुख प्रश्न उनकी बुनियादी समस्याओं को लेकर बरकरार है। इसके अतिरिक्त बढ़ती बेरोजगारी और गरीबी जैसे विषय बहुत चर्चित रहे, खाद्य वस्तुओं और जरूरत की अन्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतें भी चर्चा में रही हैं। दुर्भाग्य है कि राष्ट्रपति के सम्बोधन में संप्रग सरकार की वरीयता सूची में ये दोनों महत्वपूर्ण विषय स्थान नहीं बना सके। इस तरह देश के लाखों बेरोजगार युवकों को निराशा हुयी।

वहीं दूसरी तरफ सरकार ने चिन्ता जताते हुये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने के साथ-साथ अपने प्रिय आर्थिक सुधारों जैसे बैंकिंग, बीमा और पेंशन के क्षेत्र में सुधारों के प्रति प्रतिवद्धता जतायी। यहाँ तक की वर्ष 2004 में सत्ता में आते ही पिछली सरकार द्वारा लागू विनिवेश नीति को संप्रग सरकार त्याग दिया था, लेकिन एक बार फिर यही सरकार विनिवेश को बढ़ावा देने की घोषणा कर रही है। यहाँ तक याद किया जा सकता है की 2004 में संप्रग सरकार के सत्ता में आने से पहले राजद के साथ काफी गंभीर बहस का मुद्दा रहा है। परन्तु संप्रग सरकार उसी नीति पर चल पड़ी है। कांग्रेस नेतृत्व प्राप्त संप्रग सरकार अति उत्साह में दिखायी दे रही है, क्योंकि इस बार वे वामदलों के अवरोध से मुक्त हैं और इस तरह पिछले कार्यकाल के दौरान रूके हुये अपने सुधारवादी कार्यक्रमों को जोर-शोर से लागू करने के लिये स्वतंत्र है। परन्तु हम इन सुधारों का पहले की तरह विरोध जारी रखेंगे क्योंकि ये सुधार जनविरोधी और पूँजीपतियों के हित में है। सार्वजनिक उपक्रमों का हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिसे जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गाँधी के समय की कांग्रेस सरकार ने स्वीकार किया था। परन्तु विश्वव्यापी बढ़ते साम्राज्यवादी दबाव, भूमण्डलीकरण और निजीकरण के चलते कांग्रेस सरकार अपनी पिछली नीतियों के विरोध में चल पड़ी है।

बेशक विनिवेश जैसे शब्द से सरकार गुरेज कर रही है और इसके स्थान पर भ्रम पैदा करने वाले और अपेक्षाकृत लोकप्रिय दिखने वाले शब्द ''जनता-मालिकाना'' का प्रयोग कर रही है। राष्ट्रपति महोदया ने आगे स्पष्ट किया "सार्वजनिक उपक्रम की कम्पनियों के शेयर को हमारे देश के हर नागरिक को लेने का अधिकार है, जबकि सरकार इनके अधिकांश शेयर और नियंत्रण अपने पास रखेगी"। परन्तु सरकार ने यहाँ प्रयुक्त 'जनता' शब्द को स्पष्ट करने से परहेज किया है। निश्चिन्त रूप से लाखों गरीब और आम जनता इन सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों को लेने से दूर रहेगी। हमारे देश की 77 प्रतिशत जनता की प्रतिदिन आय महज 20 रु० है, क्या इन सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर खरीदने की हैसियत है ?सरकार पूरी तरीके से जानती है कि ये शेयर मुट्ठीभर अरबपति और खरबपति, निगमित घरानों और उच्च वाणिज्यिक ही खरीद सकेंगे। इस तरह सार्वजनिक उपक्रमों के महत्व को बहुत दूर तक और बहुत गहरे चोट पहुँचाने की योजना में सरकार है।

2004 में आयी संप्रग सरकार के साढ़े चार वर्ष के कार्यकाल के दौरान वामदलों के योगदान को स्वीकार करने या आंकने में कांग्रेस उदार नहीं रही है। ऐसे बहुत से कदम वाम दलों के दबाव में उठाये गये जो जनता के हित में थे जैसे नरेगा, जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन जीवी (वन अधिकार की मान्यता) कानून, जनसूचना का अधिकार और अन्य। इनकी मदद से समग्र विकास हो सकता है। हम चाहते है कि इनका विस्तार हो जैसे 100 दिनों के काम के अधिकार को 200 दिनों में बदला जाये और इसका लाभ शहरी गरीबों को भी मिले। परन्तु सरकार के द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया है।

राष्ट्रपति ने अपने भाषण में सामाजिक कल्याण की अनेक योजनाओं का उत्साहपूर्वक उल्लेख किया परन्तु एक भी योजना के बारे में यह नहीं सुझाया कि इन्हें कैसे लागू और पूरा किया जाये।

कुपोषण अभी भी हमारी सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या बनी हुयी है। सर्वशिक्षा अभियान नारी शिक्षा की दर में वृद्धि लाने में असफल रही है। सरकार अभी भी सकल घरेलू उत्पाद में शिक्षा के लिये 6 प्रतिशत देने की गारंटी नहीं दे पा रही है। यह एक अच्छा संकेत है कि सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे तबके के परिवार को 25 किलोग्राम चावल या गेहूँ 3/- रुपये प्रति किलों की घटी हुयी दर से देने का आश्वासन दिया है। परन्तु सबसे प्रमुख है की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सही मायने में मजबूत और व्यापक किया जाये।

महिला आरक्षण बिल को सौ दिनों में पास कराने के सरकार के घोषणा का हम स्वागत करते हैं जिसे वह पिछले 100 महीनों में पास नहीं करा सकी, वामदल हमेशा महिलाओं को पूर्ण रूप से सशक्त करने के पक्ष में रहा है।

लगातार मांग होती रही है कि गरीब किसानों को कर्ज माफी के साथ उन गरीब किसानों के बारे में जिन्होंने निजी बैंकों और साहूकारों से कर्ज लिया है के संदर्भ में सरकार अपनी योजना बताये। परन्तु राष्ट्रपति के भाषण में इस विषय पर कुछ न कहने से निराशा हुयी है।

सरकार ने अमेरिका के साथ अपनी सह-भागिता निभाने की प्रतिवद्धता जतायी है। यह विषय जनता के मध्य तीव्र आलोचना का रहा है, परन्तु सरकार अपने रवैये पर कायम है। ऐसा करके हमारी स्वतंत्र विदेश नीति प्रभावित होगी। हम चिन्तित है कि परमाणु अप्रसार संधि और व्यापक परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर के संदर्भ में अमेरिका के बढ़ते के कारण भारत सरकार क्या रवैया अपनाती है ?

अन्त में आईला तूफान के आने से पश्चिम बंगाल में मची तबाही की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। पीड़ितों के कष्ट में पूरा देश को साथ देना चाहिये। भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और हर तरह की मदद और अनुदान राज्य की पीड़ित जनता को दे।

....

संसद में 8 जून 2009 को राज्य सभा में सांसद डॉ. बरूण मुखर्जी के भाषण पर आधारित।

स्वाइन फ्लू : फैलती ग्लोबल महामारी

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 52 से अधिक लोग भारत में स्वाइन फ्लू से प्रभावित है। इनमें से दो मामले ऐसे है जो स्वदेशी है, बाकि सभी पीड़ित विदेश आये हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 12 जून 2009 तक 74 देशों की 29699 प्रयोगशालाओं ने स्वाइन फ्लू के मामले की पुष्टि की है। इससे 145 मौतें हो चुकी है। अत: यह एक वैश्विक महामारी के रूप में फैल रहा है।

"यह स्वाइन फ्लू एक नया वायरस (भ्छ) है और हम इसके प्रसार और परिवर्तन पर एक कड़ी निगरानी रख रहे हैं। इस पर हम मौसम और पर्यावरण में बदलाव के साथ गहनता से नजर रख रहे हैं, हम लोग इस वायरस के लक्ष्ण पर नजर रख रहे हैं और इसके बदलते व्यवहार का इंतजार कर रहे हैं। फ्लू से पीड़ित व्यक्ति में इसके लक्ष्ण की सक्रियता से निगरानी कर रहे हैं।" उक्त बातें एक अधिकारिक बयान में कहा।

स्वाइन इन्फ्लूएंजा (जिसे स्वाईन फ्लू, होग फ्लू और पिग फ्लू भी कहा जाता है) मेजबान जानवरों में संक्रमित एक कई विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जिवाणुओं का संक्रमण है जिसे स्वाइन इन्फ्लूएंजा वायरस कहते हैं।

स्वाइन इन्फ्लूएंजा अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, दक्षिण अमेरिका, इंग्लैण्ड, स्वीडन, इटली, केन्या और पूर्वी एशिया जैसे चीन, ताइवान और जापान में एक समान रूप पाये जाने वाला सूअर है।

स्वाईन फ्लू वायरस का सूअर से मानव शरीर में संचारण आम नहीं है और न ही यह मानव इन्फ्लुएंजा का कारण है, इससे प्राय: खून में एंटीबॉडी के उत्पादन पर असर पड़ता है। पशु का मांस यदि ठिक से पका हो तो इसके फैलने की संभावना नहीं रहती। अगर इसका प्रसारण मानव इन्फ्लुएंजा को प्रभावित करता है तो इसे जूनोटिक स्वाइन फ्लू कहते है। जो लोग सूअर का काम करते है, विशेषकर वे जो इसमें अति जोखिम के साथ कार्य करत है, उनमें स्वाइन फ्लू फैलने का खतरा ज्यादा होता है

मानव में, स्वाइन फ्लू के लक्ष्ण इस इन्फ्लूएंजा के संक्रमण होते है वह –सामान्य बिमारी है जैसे ठण्डा लगना, बुखार गले में खरास, शरीर में दर्द, सिर दर्द, खाँसी, कमजोरी और सामान्य तौर पर असहज महसूस करना है।

भारत सरकार और राज्य सरकारों को इस महामारी को रोकने के लिये तुरंत जागरूकता अभियान चलाने के साथ–साथ सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिये।

....

डॉ. बरूण मुखर्जी द्वारा

राजनैतिक टिप्पणी

शिक्षा के क्षेत्र में अमेरिकी सहयोग के लिये भारत के बढ़ते कदम

जैसा कि संप्रग सरकार दूसरी बार सत्ता में आयी है, भारत की अमेरिका के साथ कूटनीतिक भागीदारी का विस्तार रक्षा से बढ़ते हुये सुरक्षा तक या वाणिज्य से शिक्षा तक बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार अमेरिका के साथ मित्रता का नया युग शुरू हो चुका है। प्रस्तावित 'शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग' इस क्षेत्र में भारत की सर्वमान्य श्रेष्टता को कम करने का महज एक प्रयास है। 11 जून 2009 को नई दिल्ली में देश के मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल और अमेरिकी अवर–सचिव (राजनैतिक मामलों) की बैठक हुयी, जिसमें दोनों देशों के बीच शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार की योजनाओं पर नजर रखने के लिये संयुक्त कार्यकारी समूह के गठन की घोषणा की गयी। 30 देशों के ज्वाईंट वर्किंग ग्रुप से कही अधिक राजनैतिक रूप से शक्तिशाली और प्रभावकारी यह संयुक्त कार्यकारी समूह होगा, जैसा और बर्न दोनों ने स्वीकार किया। इस तरह भारत की शिक्षा क्षेत्र में अमेरिकी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और ऐसे निवेश के लागू करने में बने नियमों की पुनर्संरचना होगी।

वर्तमान में भारत प्रतिवर्ष 90,000 छात्र अमेरिका भेजता है जो दुनिया के किसी और देशों के छात्रों की संख्या से अधिक है। अब परिवर्तित योजना के तहत संप्रग सरकार भारत की धरती पर अमेरिका शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। जैसा कि सिब्बल महोदय ने भारत के शिक्षा क्षेत्र में अमेरिकी निवेश के प्रति इच्छा जताई वहीं बर्न महोदय ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विदेशियों के दखल को बढ़ाने हेतु कड़े भारतीय नियमों को अवरोध बताया। यह भी बताया गया कि कार्यकारी समूह संस्थागत शिक्षा के साथ–साथ माध्यमिक, उच्च और व्यवसायिक

शिक्षा के क्षेत्र में कड़ी निगाह रखेगा। ऐसे समय में जब हमारे शैक्षणिक संस्थान मूलभूत सुविधाओं का अभाव झेल रहे हैं अमेरिका को अपने शैक्षणिक संस्थान उन्मुक्त रूप से भारत में स्थापित करने की छूट देकर यह संयुक्त प्रयास भारत की शिक्षा जगत की गहरी चिन्ता का कारण बना हुआ है। यही नहीं विदेशियों के द्वारा देश के नौजवानों को शिक्षा देने से हमारे समाज में घोर सामाजिक असहजता के जन्म लेने का खतरा मंडरा रहा है।

सेवा कर में राहत और सेज का बढ़ता दायरा

पुराने दिनों के जमींदारी व्यवस्था की तरह ही वर्तमान समय भूमि का बड़ा हिस्सा झपटने के प्रयास में सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र) प्रमुख निभा रहा है। निर्यात वृद्धि और तथाकथित रोजगार सृजन के नाम पर सार्वजनिक धन की कीमत पर सरकार भारतीय या विदेशी कारपोरेट घरानों को अपने धंधें चलाने की आजादी दे रही है। सरकार इन सेजों को तरह-तरह के करों में भारी छूट और अनुदान देकर सार्वजनिक धन के साथ खिलवाड़ कर रही है। छोटे किसानों और गरीब मछुआरों के हजारों एकड़ जमीन अधिग्रहण सेज कानून 2005 के अन्तर्गत करके वैद्यता प्रदान कर रही है। और इस तरह अनेक सेजों का निर्माण हो रहा है। देश के अनेक हिस्सों में विरोध हो रहा है परन्तु भारत सरकार लगातार अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ रही है और अधिक से अधिक सेजों को अपनी स्वीकृति प्रदान करती जा रही है। इस समय इनकी संख्या 531 पहुँच चुकी है और 143 स्वीकृत होने की प्रक्रिया में है और इस तरह 67680 हैक्टेयर भूमि अधिगृहित की जा चुकी है।

हाल में संपन्न हुये 15वीं लोकसभा के चुनाव देश व्यस्त था और सरकारी मशीनरियाँ चुपचाप सेजों के हितों को और व्यापक करने में लगी हुयी थी। मई 2009 में सरकार ने सूचना जारी करते हुये कहा कि सेजों को अपने क्षेत्रों में सेवाकर में राहत दी जायेगी। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एण्ड कस्टम की जारी सूचना के अनुसार यह राहत बिना शर्त के इन सेजों को उपलब्ध करायी गयी है जिनमें राजस्व वापसी के तरीकों का कोई उल्लेख नहीं है।

मई 2009 से सेज विकसित करने वालों की सीमा बढ़ाकर 5000 हैक्टेयर तक की सीमा दी गयी है। इन्हें क्षेत्र के चयन की और अधिक आजादी भी दी गयी है।

सेज नियमों (दूसरे संशोधन के अनुसार), जैसा भारत सरकार के मई 2009 के अन्तिम सप्ताह में प्रकाशित गजट के अनुसार, यदि दो या अधिक क्षेत्र विलय करते हैं तो उन पर 5000 हैक्टेयर क्षेत्र तक की सीमा से सम्बन्धित नियम लागू नहीं होगा। इस तरह इस संशोधन के द्वारा सेज नियमों को भारत सरकार ने धुर्तता पूर्वक पूरे देश पर भूमि अधिग्रहण के लिये थोप दिया।

आइला तूफान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करें

गत 25 मई को उठे आइला नामक समुद्री तूफान ने खासकर पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों जैसे, उत्तरी 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना और पर्वतीय जिले दार्जिलिंग समेत कई जिलों में धन-जन का व्यापक संहार किया। इस प्राकृतिक आपदा की विनाशलीला को इन आंकड़ों से बेहतर समझा जा सकता है कि तूफान प्रभावित जिलों में कम से कम 137 लोग मारे गए, 68 लाख लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए, 9 लाख मकान मटियामेट हो गये और करीब 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि में खड़ी फसलें तबाह हो गयीं। इसके अलावा तूफान से पालतू पशुओं और जंगली जानवरों का भी भारी नुकसान हुआ। करीब 500 किलोमीटर तटबंध और सड़क क्षतिग्रस्त हो गयीं और पानी में डूब गयीं। प्रभावित लोगों के लिए रहने, खाने और पीने के पानी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी, सो उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में जीवन गुजारने को मजबूर होना पड़ा। दार्जिलिंग इलाके में बड़ी मात्रा में हुए भू-स्खलनों में अनेक जानें गयीं और संपत्ति का भारी नुकसान उठाना पड़ा। मकान और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई। हालांकि इस भीषण विनाशकारी तूफान को अब तक राष्ट्रीय आपदा नहीं घोषित किया गया है।

सकारात्मक बात यह रही कि प्रभावित लोगों की सहायता को राज्य के हर ओर से हाथ बढ़े। न केवल राज्य सरकार ने बल्कि सभी क्षेत्रों के लोगों, राजनीतिक दलों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने सहायता में अपने संसाधनों को झोंक दिया। राहत सामग्री बाढ़ से प्रभावित सुदूर क्षेत्रों में भेजी गयीं। लेकिन बावजूद इसके क्षति की तुलना में राहत कार्य कम हुए हैं। अब भी दूरदराज के इलाकों में प्रभावित लोगों तक ठीक से राहत सामग्री नहीं पहुंच पायी है।

विपदाग्रस्त लोगों की सहायता, क्षतिग्रस्त तटबंधों, सड़कों और मकानों की मरम्मत के लिए अभी भारी मात्रा में धन की आवश्यकता है। राज्य सरकार अपने संसाधनों को तो सहायता में झोंक ही रही है, उसने केंद्र से भी प्रधानमंत्री राहत कोष से 1000 करोड़ रुपये की मांग की है। अब तक 1000 करोड़ रुपये की अग्रिम सहायता दी भी गयी है और केंद्रीय टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का आकलन किया है।

केंद्र सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह बिना किसी राजनीतिक द्वेष और भेदभाव के पश्चिम बंगाल के इन तूफान प्रभावित क्षेत्रों की उसी प्रकार राष्ट्रीय आपदा घोषित कर मदद करे जैसे उसने कोशी की विनाशलीला के समय बिहार की की थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हाल के लोकसभा चुनाव में राज्य से जीत कर केंद्र में मंत्री बने और अन्य सांसद केंद्रीय राहत सहायता को राज्य तक आने देने से रोक रहे हैं। साफ है कि राज्य से निर्वाचित अधिकांश सांसद

राज्य सरकार की विपक्षी पार्टियों के हैं। ये सांसद राज्य सरकार द्वारा संसाधनों और राहत राशि के दुरुपयोग की थोथी दलील दे रहे हैं। अफसोसजनक और निंदनीय बात यह है कि जब राज्य की लाखों जनता दुर्दिन में फंसी है और उसे सहायता की जरूरत है, तो विपक्ष मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की नापाक चालें चल रहा है। चिंताजनक रिपोर्टे तो यहां तक आ रही हैं कि प्रभावित लोगों की सहायता में लगे सत्तारूढ वाम मोर्चे के कार्यकर्ताओं को विपक्षी दलों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और लालच दिया जा रहा है। वे राहत अभियान में बाधा डालना चाह रहे हैं। यह पूरी तरह से अमानवीय और अक्षम्य अपराध है। हम राजनीतिक भेदभाव से ऊपर उठकर तमाम लोगों से अपील करते हैं कि अपने आइला तूफान से पीड़ित भाई-बहनों और बच्चों की सहायता में एकजुट होकर आगे आएं और इन क्षेत्रों में जीवन को फिर से सुचारू बनाने के लिए मिलजुलकर काम करें।

हम केंद्र सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर हर प्रकार की संभव सहायता मुहैया कराएं।

सुनामी पीड़ितों की आज भी कोई सुध लेने वाला नहीं

12 जून 2009 को अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की पाण्डिचेरी कमिटी की बैठक पी. डब्ल्यू. डी. की कराइकल इन्सपेक्सन भवन में साथी मौहम्मद युसुफ की अध्यक्षता में संपन्न हुयी। बैठक में पार्टी महासचिव साथी देवब्रत बिश्वास भी उपस्थित थे।

बैठक में साथी यू मुथु, प्रान्तीय महासचिव ने लोकसभा चुनाव में राज्य में फारवर्ड ब्लॉक की भूमिका को विस्तृत रूप से बताते हुये कहा कि फारवर्ड ब्लॉक ने एक महत्वपूर्ण वामपंथ की भूमिका निभाते हुये सक्रिय रूप से वाम समर्थित पार्टियों के लिये कार्य किया तथा जिसके कारण राज्य में फारवर्ड ब्लॉक की एक विशेष पहचान स्थापित हो गयी है। इसके अलावा साथी यू मूथु ने पार्टी की विस्तृत सांगठनिक रिपोर्ट भी पेश की। उन्होंने आगे कहा कि 2004 में आये सुनामी (समुद्री तूफान) से राज्यभर में जो तबाही हुयी हुयी थी उसे बीते साढ़े चार वर्ष बीत चुके है किन्तु आज तक प्रदेश के किसानों, मछुआरों, मजदूरों की सूध लेने वाला कोई नहीं है। फिरौती के लिये विद्यार्थियों का अपहरण गंभीर रूप पकड़ चुका है। शासन, प्रशासन व्यवस्था आदि नाम मात्र की ही है। पाण्डिचेरी में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति एक गंभीर समस्या है। अत: पार्टी ने आगामी 20 जुलाई 2009 को मुख्यमंत्री के सामने धरना-प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है।

इसके अलावा बैठक अन्य साथियों ने भी अपने-अपने वक्तव्य रखें तथा 30 जून तक पार्टी सदस्यता का कार्य संपन्न कर पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में जमा कराने का निर्णय लिया गया।

फारवर्ड ब्लॉक बिहार राज्य कमिटी की सभा का समापन

आल इण्डिया फारवर्ड ब्लॉक का दो-दिवसीय 20-21 जून 2009 को बिहार राज्य कमिटी की विस्तारित बैठक एम.एल.ए. क्लब सभागार में साथी शम्भू प्रसाद शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुयी। बैठक में अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय महासचिव साथी देवब्रत बिश्वास ने भाग लिया। बैठक मे सम्पन्न हुये लोकसभा चुनाव की समीक्षा में फारवर्ड ब्लॉक के प्रदर्शन के साथ-साथ भाकपा, माकपा, माकपा (माले) के (वाम मोर्चा), आर.एस.पी. के साथ-साथ मध्य वर्गीय दल राजद, लोजपा के पतन एवं जद (यू) एवं उनके सहयोगी भाजपा का प्रदर्शन एवं कांग्रेस (ई), बसपा के प्रदर्शन पर भी गम्भीरता पूर्वक विचार किया गया।

बैठक में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस एवं स्वामी सहजानन्द सरस्वती के आदर्शों एवं स्वाधीनता आन्दोलन और किसान आन्दोलन में योगदान पर दिनांक 9 अगस्त 2009 को पटना जिला के बिहटा में स्वामी सहजानन्द सरस्वती आश्रम में एक विस्तारित शिविर का आयोजन करने का निर्णय के साथ ही नेताजी सुभाष चन्द्र बोस - स्वामी सहजानन्द सरस्वती चेतना रथ सम्पूर्ण बिहार में निकालने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में पार्टी सांगठनिक कार्यक्रमों को कार्यरूप देने के लिये विस्तारित कार्यक्रम बनाया गया। मुजफ्फरपुर एवं उत्तर बिहार के प्रभार में साथी वकील ठाकुर कोषाध्यक्ष, पूर्णिया और आरा के साथ-साथ शाहाबाद प्रमंडल का प्रभार साथी श्री नारायण सिंह, नवादा, नालन्दा का प्रभार साथी अजय, पटना, जहानाबाद, गया का प्रभार साथी आजाद को दायित्व के रूप में सौंपा गया। अग्रगामी किसान सभा का कार्य साथी चन्द्रशेखर मिश्रा एवं साथी श्री नारायण सिंह को सौंपा गया।

बैठक में पार्टी की सदस्यता की अंतिम तिथ 30 जून 2009 के आधार पर पार्टी का पंचायत /वार्ड/प्रखण्ड/ अंचल का सम्मेलन अगस्त-सितम्बर, 2009 तथा जिला सम्मेलन अक्तूबर 2009 एवं राज्य सम्मेलन नवम्बर 2009 में करने का निर्णय लिया गया। पार्टी का राज्य कमिटी का आगामी बैठक 05 जुलाई 2009 को पटना में होगी।

द्वितीय सेशन 21 जून 2009 की बैठक में पार्टी के कार्य क्षेत्र वाले 10 जिलाओं से 200 सक्रिय सदस्यों ने शिरकत की। बैठक में अतिथि के रूप

में ऑल इण्डिया छात्र ब्लॉक के राष्ट्रीय महासचिव साथी अमरेश कुमार, लोकसभा में पार्टी के प्रत्याशी साथी राम दयाल राम (मुजफ्फपुर), साथी साधु सिन्हा (जहानाबाद), साथी डॉ. शम्भू प्रसाद शर्मा (आरा), साथी मो. सदररुद्दीन (पाटलीपुत्र) तथा साथी वकील ठाकुर (कोषाध्यक्ष), साथी श्री नारायण सिंह, साथी अजय, साथी आजाद, साथी चन्द्रशेखर मिश्रा, साथी संदीप कुमार, साथी दिनेश सिंह, साथी राम बाबू सिंह, साथी चन्द्रशेखर सिंह, साथी सुभाष चन्द्र प्रसाद (अधिवक्ता), साथी एस.एस. पाण्डेय, साथी नन्द कुमार सिंह, साथी हरिओम भगत, साथी बृजनन्दन ठाकुर, साथी नवीन कुमार महतो, साथी परशुराम प्रसाद ठनठोरिया, साथी हबीब अंसारी ने भी भाग लिया।

वाममोर्चे की हार का मुख्य कारण पंचायत चुनाव की अनदेखी करना

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की बंगाल समिति की दो दिन की बैठक 7 और 8 जून 2009 को कोलकाता में पार्टी के राज्य मुख्यालय में आयोजित किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता राज्य इकाई के अध्यक्ष साथी रबिन घोष ने किया तथा डॉ. मुखर्जी, उपाध्यक्ष के अलावा अन्य सचिव सदस्य और राज्य कमिटी के जिला प्रतिनिधित्व भी शामिल थे। केन्द्रीय कमिटी के महासचिव साथी देवब्रत बिश्वास भी मीटिंग में पूरे दो दिन की बैठक के पूरे विचार विमर्श के दौरान उपस्थित थे। आरम्भ में साथी अशोक घोष, महासचिव राज्य कमिटी ने 15वीं लोकसभा में वामदलों की असफलता को इंगित किया तथा राज्य के तटवर्ती क्षेत्रों में आइला चक्रवात तूफान के कारण अप्रत्याशित आपदा का एजेंडा प्रस्तुत किया। जिला महासचिवों और जन संगठनों सहित 32 सदस्याओं ने इस विचार विमर्श में भाग लिया और 15वीं लोकसभा चुनाव में हार के कारणों के बारे में अपनी राय और सुझाव दिया। कमिटी ने आइला पीड़ितों को राहत के बारे में चर्चा किया, और साथ ही चुनाव बाद विपक्षी तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस द्वारा राज्यभर में हिंसा उकसाये जाने पर भी चर्चा किया।

हालांकि वामपंथी दलों की चुनावी पराजय के कारणों की जांच समिति का मानना है कि इसके पीछे कई कारक है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर विफल तीसरे मोर्चे के गठन का भी है और इसके साथ-साथ राज्य के कुछ विशिष्ट कारण भी है

हालांकि इससे निपटने के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये गये - औद्योगिकरण के लिये भूमि अधिग्रहण पर टकराव-भ्रम, पंचायत में भ्रष्टाचार, नौकरशाही पर अत्यधिक निर्भरता, प्रशासनिकविफलता, विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र में सामाजिक कल्याण कार्य (जैसे जन स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि), प्रशासनिक विफलता, और सत्तरूढ़ दल के सदस्यों का हत्या और बलात्कार जैसे मामलों में शामिल होना और उनका व्यवहारिक रवैया आदि। इन सब के कारण ही हमें पराजय का असंभावी मुँह देखना पड़ा, अत: इस प्रकार की उच्च डिग्री को हमें बढ़ावा नहीं करना चाहिये। मई 2008 के पंचायत चुनावों की उन्नत घंटी की आवाज को अनदेखा नहीं करना चाहिये थे। हमने इसका (मई 2008 का पंचायत चुनाव) उचित ध्यान रखना नहीं रखा जिसका परिणाम 2009 में अधिक संगीन दिखा। हमारी स्थिति को पुन: पुनर्जीवित करने का एकमात्र तरीका है 'वामपंथी', जो मेहनत जनता में अपने विश्वास को बनाये रखने के लिये जरूरी है। अत: हमलोग पुन: वाम एकता को मजबूत करेंगे और जनता में बातचीत के जरिये विश्वास पैदा करेंगे

राज्य कमिटी ने अपने दूसरे प्रस्ताव में निर्णय लिया कि जून 2009 तक सभी जिलों में लोकल-जोनल स्तर तक की सभी शाखाओं में विशेष मीटिंग करने का निर्णय किया गया जिसमें राज्य पर्यवैक्षक सम्मिलित रहेंगे।

तीसरे प्रस्ताव में राज्य कमिटी ने सभी इकाईयों को निर्देश दिया कि आइला पीड़ितों के राहत के लिये ईमानदारी पूर्वक सहायता शिविरों का आयोजन करें।

चौथे प्रस्ताव में राज्य कमिटी ने विपक्षी दलों द्वारा भड़कायी जा रही घृणा और हिंसा पर गंभीरता पूर्वक चिंता व्यक्त किय और राज्य की प्रगती के लिये सभी से में शांति और सौहार्द्ध बनाये रखने की अपील की गई।

अपने पांचवे प्रस्ताव में राज्य समिति ने निर्णय लिया है कि पार्टी की सभी इकाई 22 जून 2009 को पार्टी की 70वें पार्टी स्थापना दिवस को उचित तरीके से मनायेंगे। पार्टी इस दिन को साम्प्रदायवादी विरोधी, साम्राज्यवादी विरोधी और पूँजीवादी विरोध के रूप में मनाया जायेगा और वाम एकता के लिये देशभर में नारा दिया जायेगा।

चर्चा के दौरान अपने जवाब में साथी देवब्रत बिश्वास ने दुनिया भर में जारी साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष की व्याख्या की और इस संबंध नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा स्थापित पार्टी 'फारवर्ड ब्लॉक' की ऐतिहासिक भूमिका पर प्रकाश डाला।

सेवा क्षेत्र के बाजार बनने से समस्याओं का अंबार की संभावनाओं

3 जून 2009 को अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की उत्तर प्रदेश राज्य कमिटी की सचिव मंडल की बैठक हुयी तथा 4 जून 2009 को राज्य कमिटी की बैठक कानपुर में प्रो. राम प्रकाश श्रीवास्तव के आवास पर संपन्न हुई, जिसमें पार्टी महासचिव साथी देवब्रत बिश्वास भी उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता

साथी रामकिशोर 'डेविड' ने की।

बैठक में साथी देवब्रत बिश्वास ने उपस्थित सदस्यों को सम्बोधित करते हुये देश की वर्तमान परिदृश्य पर प्रकाश डालते हुये कहा कि सेवा क्षेत्र को बाजार का रूप देने के कारण कारण बेरोजगारी, किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या आदि बढ़ेंगी जिसके लिये हमें जन आन्दोलन करना होगा।

बैठक में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की समीक्षा की गयी। लोकसभा में सबसे अधिक संख्या में सदस्य भेजने वाला प्रदेश धर्म और जाति के झूले पर लगातार पिछले 25 वर्षो से झूल रहा है। प्रदेश की राजनीति सिद्धान्तों, कार्यक्रमो आदि पर उतना नही चलती है जितना धर्म और जाति पर परन्तु इस बार लोकसभा के चुनाव परिणाम इंगित करते हैं कि प्रदेश के मतदाताओं ने जाति और धर्म के दो पहियों की राजनीति करने वालों को किनारे करने का प्रयास किया है। मतदाताओं ने बाहुबलियों एवं दल बदलुओं तथा मौकापरस्तों को भी सबक सिखाने का काम किया है।

इस प्रदेश से सभी राजनैतिक गठबन्धनों-एन0डी0ए0, यू0पी0ए0 तीसरे मोर्चे और तथाकथित चौथे मोर्चे को काफी आशाएं थीं परन्तु प्रदेश के मतदाताओं का निर्णय सभी राजनैतिक गठबन्धनों, दलों एवं राजनीतिक विश्लेषकों तथा विचारकों के लिए हत्प्रभ करने वाला था। उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर लोकसभा सीट से पार्टी ने रामसेवक चौधरी को पार्टी का एकमात्र प्रत्याशी बनाया था। चुनाव हेतु फण्ड की व्यवस्था विभिन्न जिलों पर निर्धारित किया गया था, जिसके तहत पीलीभीत जिला कमेटी ने 6000/-, मुरादाबाद कमिटी ने 1100/- रुपये का योगदान महत्वपूर्ण योगदा दिया। राज्य में किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी, महिला आदि की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गयी तथा पार्टी की विभिन्न वर्ग संगठनों को समस्याओं के खिलाफ संघर्ष करने प्रस्ताव ग्रहण किया गया।

इसके अलावा प्रदेश की पार्टी सदस्यता की अन्तिम सूची 30 जून 2009 तक केन्द्रीय कार्यालय को भिजवाने का निर्णय लिया गया। 17 से 21 दिसम्बर 2009 को कोलकाता में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय महासम्मेलन के तहत प्रदेश में स्थानीय, प्रखण्ड, एवं जिला स्तरीय इकाइयों का गठन कर राज्य सम्मेलन सम्पन्न करने का निर्णय किया गया। जिसकी सूचना प्रदेश की आगामी बैठक में तय की जायेगी।

सभा को मुख्य रूप से प्रदेश महासचिव साथी एस.एन. सिंह चौहान ने भी सम्बोधित किया। प्रदेश की आगामी बैठक 5 जुलाई 2009 को प्रात: 11 बजे लखनऊ में होगी।

फारवर्ड ब्लॉक झारखण्ड राज्य कमिटी ने लोकसभा चुनाव की समीक्षा की

5 जून 2009 को अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की झारखण्ड की निरसा जोनल कमिटी की बैठक निरसा में हुयी। जिसकी अध्यक्षता विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने की, जिसमें 150 सक्रिय सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में पार्टी महासचिव साथी देवब्रत बिश्वास मुख्य रूप से उपस्थित थे।

बैठक में लोकसभा चुनाव परिणाम पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी। इस चुनाव में निरसा विधानसभा में खराब प्रदर्शन विस्तृत रूप से विश्लेषण किया गया। जल, जंगल और जमीन के संघर्ष के माध्यम से पार्टी संगठित हुयी थी तथा सुशान्त सेनगुप्ता और डी डी पाल जैसे शहीदों के खून से जिसे सिंचा गया था, जिनके बलिदान से विधानसभा में हम लोगों के प्रतिनिधित्व के चयनित हुये। किन्तु इसके उपरान्त संघर्ष में ढिलाई के कारण पार्टी संगठन और पार्टी में काफी मुर्छा की स्थिति आ गयी। विधान सभा में जीत के उपरान्त हमारे प्रतिनिधियों ने समाज कल्याण के काफी कार्य कराये जैसे स्वास्थ्य, सड़क आदि के क्षेत्र में काफी कार्य कराये गये, किन्तु इसके साथ-साथ जो महत्वपूर्ण भूमिका जनता के साथ जुड़े रहते हुये संघर्ष को चालू रखने का कार्य जो कार्य था वह लगभग निष्क्रिय हो गया था। अत: इस बैठक में पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जन आन्दोलन को पुन: आरम्भ करने का निर्देश दिया। आगामी 30 जून तक बूथ स्तर से चुनाव और संगठन की समीक्षा की जायेगी और स्थानीय समस्याओं को भी चिन्हित किया जायेगा।

साथी देवब्रत बिश्वास, महासचिव ने कहा कि देश में वामपंथी ताकतों को इस चुनाव में जो झटका लगा है उसका राजनैतिक और सांगठनिक विश्लेषण किया गया है। कांग्रेस के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद अर्थव्यवस्था का बाजारीकरण की प्रक्रिया तेज हो जायेगी जो देशी-विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पक्ष में होगा और मजदूर, किसान आदि सभी पर महँगायी का बोझ बढ़ जायेगा जिससे उन्हें गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। छंटनी आदि के कारण बेरोजगारी एक विकराल रूप में उभरेगा। 22 जून, पार्टी स्थापना दिवस पर साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष और वाम शक्तियों के एकीकरण हेतु आह्वान किया गया है।

राज्य कमिटी की बैठक 6 जून 2009 को हुयी जिसमें चुनाव की समीक्षा विस्तृत रूप से की गयी जो इस प्रकार है:

झारखण्ड में लोकसभा चुनाव परिणाम

झारखण्ड में इस बार लोकसभा परिणाम वामदलों के लिये काफी निराशाजनक रहा। प्रदेश की एकमात्र हजारीबाग सीट जो भाकपा के कब्जे में कामरेड भुवनेश्वर मेहता के पास थी। वे अपनी जमानत बचाने में भी असफल रहे। हालांकि इस बार फारवर्ड ब्लॉक को छोड़कर भाकपा, माकपा, भाकपा माले एवं मासस ने एक एक मोर्चा के तहत चुनाव लड़ा था लेकिन भाकपा माले के राजकुमार यादव ने कोडरमा सीट से अपनी जमानत बचा पाये। माकपा को राँची एवं राजमहल से, भाकपा को हजारीबाग एवं गिरीडीह से तथा मासस को धनबाद एवं गिरीडीह से पराजय का मुँह देखना पड़ा। अखिल हिन्द

फारवर्ड ब्लॉक धनबाद सीट से एकमात्र चुनाव लड़ा था जहाँ पार्टी प्रत्याशी साथी जनार्दन पाण्डेय को 5293 मत मिले। सबसे बड़ी चिन्ता की बात है कि फारवर्ड ब्लॉक के कब्जे वाली निरसा विधान सभा से पार्टी प्रत्याशी को 2992 मत प्राप्त हुये। जबकि मासस को निरसा से 19067 मत मिले। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि धनबाद जिले का लाल दुर्ग निरसा में पहली बार भाजपा को इस चुनाव में 54149 मत प्राप्त हुये। आगामी विधान सभा चुनाव के लिये यह खतरे की घंटी है।

झारखण्ड के 14 सीटों में 8 में भाजपा विजयी हुयी, जबकि 1-कांग्रेस, 2-झामुमो, 2-निर्दलीय तथा 1-झारखण्ड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के बाबुलाल मराण्डी ने जीत दर्ज करायी।

झारखण्ड में यूपीए एवं निर्दलीय प्रायोजित कुर्सी के फेर-बदल के खेल को जनता ने नकार दिया। यूपीए का कुनबा तास की पत्ते की तरह ऐन चुनाव वक्त बिखर गया। जिसका खामियाजा झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद को भुगतना पड़ा। सूबे में वाम दल अपनी एकता बरकरार रखने में नाकामयाब रहे जिसका लाभ साम्प्रदायिक शक्तियों को मिला।

प्रदेश में इस चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में भाजपो क आने से विधानसभा चुनाव की आहट भी सुनाई पड़ रही है। वैसे विधान सभा का कार्यकाल मार्च 2010 तक है लेकिन अवधि 18 जून 2009 को समाप्त हो रही है। इसके पूर्व या तो विधान सभा भंग करना होगा अथवा संसद से इसे आगे बढ़ाने के लिये मंजूरी लेनी होगी। इस परिस्थिति में हमारी पार्टी को भी विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग जाना होगा।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 30 जून 2009 तक पार्टी सदस्यता की अंतिम सूची केन्द्रीय कार्यालय में जमा करा दी जायेगी। पार्टी महासम्मेलन के अंतर्गत राज्य सम्मेलन की तैयारी के लिये जिलेवार विभिन्न प्रभारी नियुक्त किये गये।
साथी अपर्णा सेनगुप्ता – पूर्वी सिंह भूम, धनबाद और जमशेदपुर, साथी हंजला बिनहक – बोकारो और गिरीडीह, साथी अरूण मण्डल – जामताड़ा, साथी जनार्दन पाण्डेय – शेष सभी जिलों के प्रभारी नियुक्त किये गये।

मजदूर संगठन, छात्र संगठन, युवा संगठन एवं महिला संगठन आदि पार्टी की प्रत्येक वर्ग संगठन को पुनः संगठित कर विशेष कदम उठाने का निर्णय लिया गया। 7 जुलाई 2009 को मैथान में पुनः अगली बैठक में सभी कार्यकलापों की जाँच का निर्णय लिया गया।

इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीन की सटीकता पर गंभीर संदेह

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की तमिलनाडु राज्य कमिटी की बैठक 13 जनू 2009 को थंजावुर में संपन्न हुयी। मीटिंग में राज्य के अध्यक्ष एवं पार्टी के वयोवृद्ध साथी एण्डी थेवर के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट किया गया।

इससे पहले जिला कमिटी ने निदामंगलम, चितामल्ली, रोयापुरम में दो जगह, चेत्तीचत्तरम और थंजावुर के आस-पास कालाचेरी के गांवों में थंजावुर जिला महासचिव साथी मुरूगनंधम और थिरूवोर जिला सचिव साथी वैथीयालींगम द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न किया गया। साथी पी.वी. कादिरवन, राज्य महासचिव, ने पार्टी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, तथा सभा में वित्तीय सचिव साथी पी.एस. जयरामन, एम. महेश्वरन, एन राजशेखरन, किसान नेता इंजीनियर आर. माया थेवर, यूथ लीग सचिव साथी के. सुब्बुराज, टीयूसीसी के सी. पुलुसामी और सेथुरामन और अन्य कमिटी सदस्यों ने भी अपने वक्तव्य प्रस्तुत किये।

राज्य कमिटी की मीटिंग दोपहर 2 बजे की गयी। मीटिंग की अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष साथी वी.एस. नवामनी ने किया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव साथी देवब्रत बिश्वास ने केन्द्रीय सचिव मण्डल के निर्णयों से अवगत कराया और पार्टी स्थापना दिवस 22 जून के महत्व को विस्तारपूर्वक बताया।

साथी बिश्वास ने पार्टी की संगठनात्मक गतिविध्यिों के बारे में और लोकसभा चुनाव के बाद देश की राजनतिक स्थिति के बारे में भी विस्तार से बताया। इसके लिये मीटिंग में निम्नलिखित प्रस्ताव ग्रहण किया गया :
(1) इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में सटीकता के गंभीर संदेह है, भारत निर्वाचन आयोग को इस मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिये; (2) कचवीरू द्वीप श्रीलंका के कब्जे से वापस ले लेना चाहिये; (3) एलकेजी से लेकर उच्च शिक्षा में लिये जाने वाले सभी प्रकार के चंदों पर रोक लगानी चाहिये; (4) लिट्टे और श्रीलंका सैनिकों के बीच युद्ध में पीड़ित सभी तमिल लोगों को सुरक्षा, भोजन और सामान्य सुविधायें मुहैया करानी चाहिये; (5) नेवेली लिंगनाइट कारपोरेशन में ठेकेदार मजदूरों को नियमित किया जाना चाहिये; (6) साथी पसुम्पन पाण्डियन को पार्टी से निकाल दिया जाये, साथी मंजू गणेश और साथी सेलथिस प्रभु को किसी प्रकर की उचित उत्तर न देने के लिये उन्हें नोटिस जारी किया जाना चाहिये; (7) लोकसभा चुनाव में एआईएडीएमके के संतोषजनक विजय के लिये अपने कार्य से संतुष्ट है।

इसके अलावा सभी जिलों, शहरी और ब्लॉक स्तरीय सम्मेमलन का आयोजन की तिथिया निर्धारित की गयी।

आल इण्डिया यूथ लीग पश्चिम बंगाल
राज्य कमिटी की सभा का समापन

ऑल इण्डिया यूथ लीग की बंगाल राज्य कमिटी की बैठक 12 जून 2009 को राज्य कार्यालय में हुयी। जिसकी अध्यक्षता कमिटी के राज्य अध्यक्ष साथी अजय अग्निहोत्री ने की। मीटिंग में सर्वप्रथम आयला के कारण पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्सों दार्जिलिंग में हुये वाम जनतांत्रिक लोगों की मौत पर श्रद्धांजलिपूर्वक 1 मिनट का मौन रखा गया।

साथी अनिर्बन चौधरी, महासचिव बंगाल राज्य कमिटी सांगठनिक कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

हाल ही में संपन्न 15वीं लोकसभा चुनाव में वामदलों की पराजय को लेकर राजनैतिक समीक्षा भी कि गयी। मिटींग में निम्नलिखित टिप्पणी की गयी–

- प्रस्तावित तीसरा मोर्चा को मतदातों ने बुरी तरह अस्वीकार कर दिया।
- चुनाव आने के समय भारत–अमेरिका परमाणु समझौते को लेकर केन्द्र में सरकार से समर्थन वापस लेना मतदाताओं को नागवार गुजरा।
- परमाणु मुद्दे पर जनता को फुसलाना विफल रहा।
- घमंड और भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल के कुछ नेताओं में था, जिन्होंने जनता से दूरियाँ बनाये रखा।
- पश्चिम बंगाल में सरकारी कार्यालयों में काम में ढिलाई और नौकरशाहों पर अधिक निर्भरता हार का कारण रही।
- औद्योगिकरण के नाम अवैध तरीके से भूमि हथियाना।
- सच्चर कमिटी की रिपोर्ट का प्रभाव सरकार के खिलाफ।
- बुद्धिजिवियों में श्रेणियाँ।
- प्रिन्ट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया का वामविरोधी गलत प्रचार।

राज्य कमिटी ने महसूस किया कि इस राजनैतिक सुनामी में अपने नेताओं में नये खून का संचार करना आवश्यक है, इसके लिये जन संबंध बनाये रखना, व्यापक नेतृत्व क्षमता और सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता और त्वरण लाना आवश्यक है।

मीटिंग में निम्नलिखित कार्यक्रमों का प्रस्ताव ग्रहण किया गया–

1. प्रत्येक जिला की विस्तारित मीटिंग जुलाई माह में आयोजित की जायेगी।
2. आम लोगों जुड़ें रहने के लिये कोलकाता में 1 अगस्त 2009 को सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा।
3. 5 और 6 अगस्त 2009 को मालदा जिला में एक वर्कशॉप का आयोजन किया जायेगा।
4. अगस्त और दिसम्बर 2009 के बीच सदस्यता अभियान पूरे पश्चिम बंगाल में चलाया जायेगा।
5. आयला पीड़ितों के लिये राहत कार्य किये जायेंगे।

चुनावी माहौल में तृणमूल कांग्रेस की हिंसात्मक गतिविधियों के मद्देनजर बंगाल की वामदलों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा

वाम मोर्चे के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल ने श्री गोपाल कृष्ण गाँधी, महामहिम राज्पाल पश्चिम बंगाल से मुलाकात की और उन्हें पश्चिम बंगाल की सूचना देते हुये लोकसभा चुनाव के पश्चात् विपक्षी तृणमूल कांग्रेस द्वारा की जा रही क्रूर हिंसा से अवगत कराया।

अँग्रेजी में लिखित इस ज्ञापन का हिन्दी रूपान्तरण इस प्रकार से है:

माननीय महामहिम जी, दिनांक 18 जून 2009

राज्यपाल पश्चिम बंगाल,

राज भवन, कोलकाता।

महामहिम जी,

हम, पश्चिम बंगाल विधानसभा के वाम मोर्चा के सदस्य आपसे तृणमूल कांग्रेस और उसके सहयोगियों संगठनों जैसे माओवादी और उसके

राजनीतिक सहयोगी जैसे कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव के पश्चात् की जा रही राज्यभर में क्रूर हिंसा और आतंक पर गहरी चिंता प्रकट करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा के तुरन्त बाद पूरे राज्यभर में इन शक्तियों ने राज्य में अराजकता और अव्यवस्था का खूनी हिंसा की एक मूर्खतापूर्ण सफर शुरू कर दिया। तृणमूल कांग्रेस और उसके सहयोगी जनतांत्रिक अधिकारों का दुरूपयोग कर रहे है और वे राज्य की लोकतांत्रिक माहौल को खतरे में डालकर घृणात्मक कार्य को अंजाम दे रहे हैं।

इस लोकसभा चुनाव में वामपंथ ने 2.37 प्रतिशत वोट प्राप्त किये जो विपक्षी गठबंधनों से कम है। हम इस प्रकार के चुनाव परिणाम के पीछे के कारणों की गहराई में नहीं जा रहे हैं। वाम मोर्चे ने लोकतंत्र की सच्ची भावना से जनादेश को स्वीकार कर लिया है।

आम चुनावों के तुरंत बाद अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा से पश्चिम बंगाल के दोनों हिस्से बूरी तरह प्रभावित हुये है। इस चक्रवात आइला में लगभग 140 लोगों की जान चली गयी, लाखों लोग बेधर हो गये, लाखों घर बर्बाद हो गये। दार्जिलिंग की पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन खिसकने से हजारों लोगों को नुकसान हुआ है। राज्य की जनता इस विपत्ती से निपटने के लिये चुनौतीपूर्ण पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिये आगे आयी है।

हालांकि, चक्रवात प्रभावित लाखों लोगों को दरकिनार करते हुये, विपक्षी दलों ने अमानवीय वयवहार करते हुये स्वयं को लोगों को सजा देने की वकालत में खड़ा हो गया है।

इन क्रूर फासीवादी जैसे हमलों से बंगाल में विपक्ष की जीत के पश्चात् इस प्रकार जश्न मनाने के रवैये उसके उसके मनोदिशा का पता चलता है।

हम इसी प्रकार की 1970 के फासीवादी आतंक की याद दिलाना चाहते हैं कि जब सीपीआई (एम) और अन्य वामदलों के 1200 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी गयी थी। जिसमें फारवर्ड ब्लॉक के अध्यक्ष और वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी साथी हेमन्ता कुमार बासु तथा सीपीआई (एम) के राज्य इकाई के सदस्य एवं वयोवृद्ध नेता साथी जिवन मायती की भी निर्मम हत्या कर दी गयी थी।

ऐतिहासिक 1977 के चुनाव में जनविरोधी सत्ताधारी कांग्रेस की पराजय को राज्य ने देखा है।

आज भी उस समय के विधानसभा चुनाव के अतिम परिणाम ज्ञात है, साथी प्रमोद दासगुप्ता और साथी ज्योति बसु, जिसमें किसी भी जवाबी कार्यवाही न करने की अपील बार-बार की गयी थी।

वाममोर्चे की सत्तसीन के पश्चात्, राज्य में कहीं भी विपक्षी नेताओं पर हमल या मारपीट नहीं की गया, या उनके घरों में आग नहीं लगायी गयी, या उनकी पार्टी कार्यालयों को ध्वस्त या जलाया नहीं गया। यह केवल वाम मोर्चा ही जिसने विपक्ष के अधिकारों को समय-समय पर सम्मानित किया है। जनता ने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत सत्ता के विरुद्ध वामविरोधी ताकतों को वोट देने के लिये एकत्रित हुये।

परन्तु इसके विपरीत राज्य में विपक्षी नेताओं ने राज्य में अपने आस-पास इस प्रकार की अनुमति दी। वे 'शांति' चाहते है, लेकिन हथियारों से लैसे केन्द्रीय मंत्रियों एवं सांसदों सहित उनके अनुयायियों ने भड़काने का खुलेआम हिंसा को जारी रखने के लिये उत्तेजित कर रहे हैं। पूर्वी मेदिनीपुर जिला के खेजुरी (वर्तमान में केन्द्रीय मंत्री का क्षेत्र) में तृणमुल सांसद ने खुलेआम चेतावनी दी है कि कोई ऊँचा लाल झण्डा नहीं लगायेगा। सैकड़ों श्रमिक खेजुरी छोड़ने के लिये मजबूर हो रहे हैं, पार्टी कार्यालयों को जलाया जा रहा है, महिलाओं को पीटा गया।

तृणमूल के गुण्डों और माओवादियों ने पुलिस द्वारा हिंसा रोकने पर पुलिस टुकड़ी और पुलिस थानों पर भी हमला किया। वे लोग बंदूक की नोक पर राज्य की कानून व्यवस्था को बर्बाद कर देना चाहते हैं।

बड़ी दु:ख के साथ हमें यह जमा करा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना 2 मार्च 2009 के दिन ही विपक्षी गुटों ने हमारे 53 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी, जिसमें 2 फारवर्ड ब्लॉक के कार्यकर्ता थे तथा 51 सीपीआई(एम) के कार्यकर्ता थे। हमारे साथी हर रोज मारे जा रहे हैं। हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को बलर्पूक अपना घरबार छोड़ने के लिये मजबूर किया जा रहा है।

जैसा कि आप जानते हैं कि बंधूकधारी माओवादियों ने पहले ही पश्चिम मेदिनीपुर जिले के लालगढ़ पर कब्जा कर लिया है और आगे की विस्तार रणनीति की योजना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। माओवादियों ने अपनी मंशा खुले तौर पर जाहिर कर दी है कि वे पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री की हत्या कर देंगे। हम आपको पुन: याद दिलाना चाहते है कि 2 नवम्बर 2008 को सलबानी में लेण्डमाईन बिछाकर ट्रीगर द्वारा विस्फोट करके माओवादियों ने हमारे मुख्यमंत्री को मारने की कोशिश की थी। लेकिन वे बच बाल-बाल बच निकले। लेकिन तृणमूल सुप्रीमो का रवैया भयावह था। उन दिनों तृणमूल सुप्रीमो ने कोलकाता में एक रैली में कहा कि मुख्य मंत्री पर यह विस्फोट आँखें खोल देने वाली थी और चेहरा बचाने का एक नाटक था। इस तरह के भाव चौंकाने वाला था। इतना ही नहीं मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता द्वारा राज्य के मुख्य मंत्री पर इस बर्बर हमले पर घिनौना खेल खेला बल्कि योजना बनाने के लिये शुकुन पहुँचाने वाला था।

यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि कार्पोरेट मीडिया के एक भाग ने बेशर्मी की हदें पार करते हुये हमलों, हत्याओं और आगजनी को दिल खोलकर समर्थन दिया। जनता पर हमले के लिये लोगों को बरगलाने के लिये एक घिनौनी कहानी को योजनावद्ध किया गया। पिछले कुछ वर्षो के इतिहास को छोड़ दे तो, मीडिया अपने पुराने अनुभवों को याद करे कि बंगाल में मीडिया कांग्रेस के राज में कितनी पीड़ित थी। 1972 में लोकतंत्र की तबाही पर मीडिया काफी उत्साहित थी, बाद में आपातकाल के काले दिनों में जीवन के कुछ 'प्राइम टाइम' अपमानजनक तरीके से सलाखों के पीछे गुजारने पड़ा था।

हम, हमपंथी किसी भी परिस्थिति में हमलों के आगे झुकेंगे नहीं। चाहे में कितनी जिंदगियां कुर्बान करनी पड़े, कितनी ही हमें क्षति पहुँचे, हम मजबूती के साथ जनता के साथ खड़े रहेंगे और लोकतंत्र और मानव अधिकार की रक्षा के लिये लड़ते रहेंगे।

हम स्पष्ट शब्दों में तृणमूल कांग्रेस और सहयोगियों द्वारा किये जा रहे आतंकवादी रवैये की निंदा करते हैं। हमें खुशी है कि राज्य में सभी तबके लोग इनके विरोध में खुलकर सामने आ गये है। इसके अलावा विपक्ष द्वारा फैलायी जा रही हिंसा के खिलाफ राज्य सरकार के उपायों का स्वागत करते हैं।

हम मांग करते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा पश्चिम बंगाल में की जा रही हिंसा में रियायत को रोका जाये।

हम प्रार्थना करते हैं कि अपने योग्य कार्यालयों को विपक्ष द्वारा की जा रही लोकतंत्र के विरूद्ध कार्यवाहियों को रोकने का प्रयास किया जाये।

उससे पहले हम यह प्रार्थना करते है कि राज्य की जनता की जीवन रक्षा के लिये, धन की और लोकतंत्र के अधिकारों की रक्षा के लिये राज्य सरकार के साथ आवश्यक सहयोग किया जाये।

शुभ कामनाओं के साथ

आपके आज्ञाकारी।

संलग्नक :

1. बर्बर हमलें में मृत 53 साथियों की सूची।
2. मृत 7 लोगों की सूची (पुलिस अधिकारी एवं कार्यरत अधिकारीगण)।
3. सांसद सुधेंधु अधिकारी द्वारा भड़काऊ भाषण के उद्धरण।
4. माओवादी नेता विकास के एक टी.वी. चैनल में दिया गया साक्षात्कार।
5. हिंसा से संबंधित फोटोग्राफ और सीडी।

पराजय के लिये राजनीतिक और संगठनात्मक कारक मुख्य कारण

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की दिल्ली राज्य कमिटी की मीटिंग मंगोल पुरी में 31 मई 2009 को आयोजित की गयी। मीटिंग की अध्सयक्षता राज्य कमिटी के अध्यक्ष साथी डी.एन. झा ने कि। मीटिंग में केन्द्रीय सचिव साथी जी. देवजरान जी मुख्य रूप से उपस्थित थे। राज्य कमिटी महासचिव साथी धर्मेन्द्र कुमार वर्मा ने संगठनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत किया।

साथी जी. देवराजन ने सभा में केन्द्रीय सचिव मण्डल में 18 मई 2009 को ग्रहण किया गया प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि राज्यों की संगठनात्मक और राजनीतिक कारक चुनाव में पराजय के मुख्य कारण थे। नंदीग्राम और सिंगुर की घटना से वाम विचारधारा वाली जनता को काफी हतोत्साहित होना पड़ा। केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और वामदलों के बीच का विरोध वामदल की हार का मुख्य कारण बनी। उन्होंने आगे कहा कि हमें इस पराजय से सबक सीखना होगा और समय रहते इसमें सुधार आवश्यक है।

साथी धर्मेन्द्र कुमार वर्मा, महासचिव दिल्ली प्रदेश ने बताया कि दिल्ली में फारवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी साथी अजय मित्तल को 1682 मत प्राप्त हुये, लेकिन ताकत, पूँजीवादी और घृणित राजनीतिक के बीच फारवर्ड ब्लॉक अपनी एक स्वच्छ छवि के कारण पहचान बनाने में कामयाब रही। साथी डी.एन. झा ने पार्टी के अन्य साथियों का सहयोग देने के लिये धन्यवाद दिया।

इसके अलावा सभा में साथी पी.एन. द्विवेदी, साथी महेश गुप्ता, साथी मनोज पासवान, साथी अनिल सांगवान, साथी केशव, साथी महादेव गुप्ता, साथी अजय मित्तल, साथी डॉ. एस.के. बिश्वास आदि ने भी अपने-अपने वक्तव्य रखे।

इतिहास के एक विस्मृत अध्याय की वापसी : 'फारवर्ड ब्लॉक'

अतुल कुमार

इतिहास में घटी कोई सामान्य सी ऐसी घटना, जिस पर उस समय हमारा ध्यान नहीं जाता, कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, इसका अहसास हमें बाद में ही होता है। लेकिन तब तक समय बीत चुका होता है और हमारे सामने उस घटना के बारे में संस्मरण सुन-पढ़कर या अपने मनो-मस्तिष्क की कल्पना की उड़ानों से स्पर्श करने के अलावा कोई अन्य तरीका नहीं रह जाता है कि उस बारे में हम जाने समझें। लेकिन उन्हीं घटनाओं में कई चीजें ऐसी भी होती हैं, जो कालान्तर में हमारे

सामने आश्चर्यजनक रूप से आ जाती है और वह क्षण किसी अजूबी घटना के समान विस्मयकारी होती है। यह हमारे मन में रोमांच का संचार करती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अमर सेनानी सुभाषचन्द्र बोस की एक ऐसी ही थाती पूरे 70 वर्षों के बाद देश और दुनिया के सामने आ जाने का अनुभव भी इसी तरह से रामांचकारी है। खासकर आजादी के बाद वाली पीढ़ियों के लिये जो सुभाष को नाम और उनके करिश्मायी कारनामों के कारण ही जानती है। सुभाष बाबू की वह थाती है उनके संपादन में प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका 'फारवर्ड ब्लॉक'।

इतिहास के पन्नों में झांकने पर पता चलता है कि 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस में गाँधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष ने कांग्रेस के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता। लेकिन इसके बाद कांग्रेस के अंदर कलह इस कदर बढ़ी और सुभाष और उनके अध्यक्षीय कामकाज पर पार्टी के अन्य नेताओं का दबाव और हस्तक्षेप इतना बढ़ने लगा कि उनके लिये संगठन का कामकाज आगे जारी रखना भी मुश्किल हो गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की ओर से उसी सम्मेलन में एक प्रस्ताव यह भी लाया गया कि पार्टी के प्रेसिडेंट गाँधी जी से पूछे बिना कोई नयी नीति या नया कामकाज नहीं कर पायेंगे। इस प्रकरण का आश्चर्यजनक पहलू यह रहा कि जिन कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों ने कांग्रेस के दक्षिणपंथियों के खिलाफ राष्ट्रपति (आजादी के पहले कांग्रेस अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहा जाता था) के चुनाव में सुभाष का साथ दिया था, उन्हीं में से कम्युनिस्टों ने इस बाद वाले प्रस्ताव में वोट देकर सुभाष बोस का हाथ बाँधने में मदद की। सोशलिस्टों ने इस प्रस्ताव पर मतदान का बहिष्कार कर पार्टी में सुभाष विरोधियों की ही एक तरह से मदद की थी।

इसके बाद जो घटनायें घटित हुयी उनमें सुभाष का गाँधी से मतभेद बढ़ता गया और कांग्रेस में गाँधी समर्थकों की बढ़ी संख्या के कारण बाद में सुभाष पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर उन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से गठित की। यह पार्टी द्वितीय विश्वयुद्ध में सीधे हस्तक्षेप करते हुये अँग्रेजों के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलने के पक्ष में थी। लेकिन तब तक न तो गाँधी और न ही कांग्रेस इसके लिये तैयार हो पाये थे। हालांकि 1942 में गाँधी जी को इस रणनीति को अपनाकर अँग्रेजों के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलना पड़ा था और 'भारत छोड़ो आन्दोलन'' शुरू करना पड़ा था। लेकिन तब काफी देर हो चुकी थी और कम्युनिस्ट मास्को का रूख भांप एक बार फिर पलटी मार चुके थे। कम्युनिस्टों ने हिटलर द्वारा सोवियत संघ पर हमले के कारण ब्रिटेन का साथ देना उचित समझा था, जो रूस के साथ था और हिटलर के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन सुभाष बोस उससे पहले ही 1941 में भारत छोड़ जर्मनी होते हुये जापान जा पहुँचे थे और आजाद हिन्द का गठन कर वह वहाँ से दिल्ली के लिये कूच कर चुके थे।

सुभाष के कांग्रेस से अलग होने और फिर भारत छोड़ने के बीच भी घटनायें घटी थीं और उन्हीं में से एक था 'फारवर्ड ब्लॉक' नाम से साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन, जिसमें भारत की भविष्य की तस्वीरें उकेरी जा रही थी। इस पत्रिका मेमं आजाद होने के बाद भारत के पुनर्निर्माण की रणनीति, उसमें चलने वाली किसान, मजदूर, अर्थ, उद्योग, समाज, राजनीति आदि के बारे विभिन्न नेताओं और विचारकों के लेख प्रकाशित हुये थे और आजादी की लड़ाई की अपनी रूपरेखा भी निरूपित की जा रही थी। जाहिर है यह पत्रिका ब्रिटिश शासकों की आंखों में खटकने लगी। फॉरवर्ड ब्लॉक के इन ऐतिहासिक अंकों को सहेजकर फेमिसाइल रूप में पुनर्प्रकाशित किया है कोलकाता के लोकमत प्रकाशनी ने। इसकी प्रस्तावना लिखी है 'फारवर्ड ब्लॉक' पार्टी के पश्चिम बंगाल इकाई के महासचिव 82 वर्षीय अशोक घोष ने। श्री घोष ने ही इस पत्रिका के अंकों को संग्रह किया और उसे व्यवस्थित कर प्रकाशित कराया है।

घोष की प्रस्तावना के अनुसार, सुभाष चन्द्र बोस के संपादन में पार्टी के मुखपत्र के रूप में साप्ताहिक फारवर्ड ब्लॉक पत्रिका का पहला अंक 5 अगस्त 1939 को निकला और यह 1 जून 1940 तक लगातार चला। लेकिन सुभाष के भारत छोड़ने और द्वितीय विश्वयुद्ध में जापान-जर्मनी की ओर से लड़ाई में हिस्सा लेने के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें देश द्रोही करार दे दिया और इस पत्रिका की देश में उपलब्ध सभी प्रतियों को जब्त कर उन्हें नष्ट कर दिया। इस तरह अंग्रेजों की नजर में भारत से सुभाष बोस के साथ ही उनकी इस पत्रिका का भी सफाया हो गया। 1 जून 1940 के बाद फारवर्ड ब्लॉक का अंक 3 अगस्त 1940 तक बंद रहा। 3 अगस्त को इसका अगला अंक निकला। घोष ने इसे फारवर्ड ब्लॉक का दूसरा संस्करण कहा है। अब तक प्रकाशित हो रहे फारवर्ड ब्लॉक के पहले पृष्ठ पर संपादक के रूप में सुभाष चन्द्र बोस का नाम प्रकाशित होता था लेकिन दूसरे संस्करण के 1 से लेकर 8 अंक तक संपादक के रूप में शांति रंजन चटर्जी का नाम छपा। घोष लिखते है कि यह वही शांति रंजन थे जो सुभाष से मिलने काबुल उस समय के बाद गये थे, जब 17 जनवरी 1941 को सुभाष बाबू अँग्रेजों की नजर से छिपकर भारत से निकल गये और काबुल पहुँचे थे। वहां से शांति रंजन चटर्जी नेताजी द्वारा लिखित दस्तावेज 'काबुल थिसिस' लेकर भारत वापस लौटे थे। इस थिसिस का शीर्षक था, 'द जस्टिफिकेशन ऑफ फारवर्ड ब्लॉक'। इसमें तात्कालिक राजनीतिक और दार्शनिक नोट लिखे गये थे। फारवर्ड ब्लॉक के अंक 9 पर संपादक के रूप में लाला रॉय का नाम छपा और सुभाष का नाम यहाँ संस्थापक के रूप में प्रकाशित हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से 3 अगस्त 1940 के बाद का अंक श्री घोष को कहीं उपलब्ध नहीं हो सका।

इतिहास में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें एक खास बिन्दु पर हम अपने स्तर से समाप्त मान लेते है, लेकिन असल में वह उस चीज या घटना का प्रस्थान बिन्दु होता है। दमनात्मक कार्यवाहियों से जनांदोलन और मजबूत होते हैं। जो चीजें एक बार अस्तित्व में आज जाती हैं, उसे प्रकृति से नष्ट करना मुश्किल है। यही बात सत्ता के मद में चूर लोक समझ नहीं पाते हैं। अंग्रेज भी इसे नहीं समझ पाए। फारवर्ड ब्लॉक पत्रिका सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक पुस्तकालयों और बुक स्टॉलों, विभिन्न पार्टियों के दफ्तरों से नष्ट हो गयी। लेकिन लोक मानस में तो यह स्थापित हो चुकी थी।

घोष ने लिखा है उन्होंने इस पत्रिका के अंकों को एकत्रित करना शुरू किया। ये अंक देश में कहीं नहीं थे लेकिन विदेशों में उसी समय वितरित हुये अंक मिले। 1998-99 में नेताजी जन्म शताब्दी के दौरान उन्होंने इसे पुन: प्रकाशित करने का प्रयास शुरू कर दिया। लेकिन जब उन्होंने इसे क्रमवद्ध किया तो पता चला कि इसमें से कई अंक अनुपलब्ध हैं। घोष के मुताबिक, कुछ वर्षों बाद श्रीमती रामेन डे ने जर्मनी से फोन किया और उन्हें बताया कि इस पत्रिका के कई अंक उनके पास उपलब्ध हैं। श्रीमती डे ने उन अंकों को उन्हें सौंप भी दिया। नेकिन घोष को फिर निराशा तब हाथ लगी जब पता चला कि अनुपलब्ध अंकों से कुछ तो उन्हें मिल गये लेकिन तब भी अंक संख्या 38, 39, 40 और 41 अनुपलब्ध ही थे। श्रीमती डे के पति श्री रामेन डे सुभाष चन्द्र बोस द्वारा स्थापित युवा संगठन 'बंगाल वॉलिंटियर' के सक्रिय लड़ाका दस्ते के सदस्य थे।बाद में वह जर्मनी जाकर बस गये; अशोक घोष ने तब नेशनल लाइब्रेरी, कोलकाता से संपर्क किया,

जहाँ जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पत्रिका के सभी अंकों का एक सेट मिल गया। दरअसल अंग्रेज सुभाष बोस के साथ ही उनकी पार्टी और पत्रिका को भी अपने साम्राज्य के लिये खतरा मानते थे इसलिये पुलिस ने 1942-43 के दौरान देशभर में फारवर्ड ब्लॉक के दफ्तरों पर छापा मारकर पार्टी के सारे दस्तावेजों को जला डाला, दफ्तरों को तोड़ डाला और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एक बार फिर 1947-49 के दौरान भी वही क्रूरता दिखाई। लेकिन इसकी कुछ प्रतियाँ जहाँ-तहां फिर भी बची रहीं।

इस पत्रिका में नेताजी वाम एकता पर जोर देकर ऐसे विचार रखने वाले पहले भारतीय राजनीतिक विचारक बने। फारवर्ड ब्लॉक पत्रिका में उस समय देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय तमाम धाराओं के नेताओं के तो लेख प्रकाशित होते ही रहते थे, साथ ही अनेक नामी-गिनमी हस्तियाँ भी इनमें स्थान पाती थी। इनमें गुरूदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, किसान नेता सहजानन्द सरस्वती, कांग्रेस नेता हुमायूं कबीर, वैज्ञानिक मेघनाद साहा, संविधानविद् हरि विष्णु, कामथ, विख्यात साहित्यकार नीद सी. चौधरी, कांग्रेस नेता और कलाकार नन्दलाल बोस, विख्यात क्रांतिकारी मन्मथनाथ गुप्त, महापंडित राहुल साकृत्यायन सरीखे नेता शामिल थे। सुभाष ने 1930 में ही लेफ्ट कंसोलिडेशन कमिटी का गठन किया था जिसकी प्रासंगिकता अब करीब 75 साल बाद और अधिक प्रतीत होने लगी है।

पत्रिका के पहले अंक में ही 'ह्वाई फारवर्ड ब्लॉक' शीर्षक से संपादकीय लिखकर सुभाष ने अपनी गतिविधियों के बारे में स्पष्ट कर दिया। जो लोक और संगठन फासीवाद के प्रति सुभाष का रूझान होने का प्रचार करते हैं, उन्हें पहले ही अंक में प्रकाशित अमियनाथ बोस का लेख फासिज्म इन इण्डिया और चाईना फाईट इंपीरियलिस्टिक जापान पढ़ लेना चाहिये। पत्रिका में प्रकाशित लेखों से भी आईने की तरह साफ हो जाता है कि सुभाष का रूझान पूरी तरह से वामपंथी प्रगतिशील राजनीति की ओर थे। वह देश में तमाम ऐसी धाराओं की एकजुटता चाहते थे। इसी क्रम में दूसरे अंक में ही सोशलिस्टों ऐ एकता का अपील करता हुआ निहारेन्दु दत्त मजूमदार का लेख प्रकाशित हुआ था। तीसरे अंक के संपादकीय में सुभाष ने अपने आलोचकों को तर्कपूर्ण जवाब दिया है तो रवीन्द्रनाथ टैगोर का संबोधन छापा। इसमें 24-25 मार्च 1940 को विजिगापटम में आयोजित ऑल इण्डिया किसान कांफ्रेंस में राहुलजी का अध्यक्षीय भाषण दस्तावेज के तौर पर विद्यमान है। पत्रिका में देश-दुनिया की तमाम समस्याओं के साथ भारत की विदेश नीति, मजदूरों के सवाल आदि पर भी महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किये जाते थे। इसी अंक में उन्होंने अपने ऊपर हुयी अनुशासनात्मक कार्यवाही का जवाब दिया है और फारवर्ड ब्लॉक से जुड़ने की अपील की। चौथे अंक में जर्मन-सोवियत पैक्ट, वर्धा स्कीम की आलोचना आदि विचारोत्तेजक लेख उस समय की राजनीतिक से ही भरे लेख जैसे हैं। महात्मा गाँधी के 70 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में भी पत्रिका में छपे संपादक में बधाई के तौर पर एक लेख लिखा गया था। इसका उल्लेख यहाँ इसलिये जरूरी है कि महात्मा गाँधी के साथ मतभेदों के कारण ही सुभाष को कांग्रेस से अलग होना पड़ा था। दो खण्डों में प्रकाशित इस फेमिसाइल के दूसरे खण्ड में अंक संख्या 22 उपलब्ध नहीं है तो अंक 23 दो बार संकलित हो गया है।

कुल मिलाकर पत्रिका के सभी उपलब्ध अंकों का दो खण्डों में प्रकाशित फेमिसाइल संस्करण ऐतिहासिक शोध के लिये महत्वपूर्ण है, जिसको उद्घृत किये बिना आजादी की लड़ाई के दौरान के वैचारिक विमर्श को समग्रता में समझा नहीं जा सकता। साथ ही इसे भारतीय पत्रकारिता के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में भी उल्लेखित करना जरूरी है, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय पत्रकारिता ने जो राष्ट्रीयतावादी और साम्राज्य विरोधी स्वरूप ग्रहण किया, उसकी कोई भी चर्चा 'फारवर्ड ब्लॉक' के बिना पूरी नहीं हो सकती।

लालगढ़ में प्रशासनिक कदम लिया जाये : वाम फ्रंट

पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा ने सरकार से लालगढ़ में शांति बहाल करने और वाम कार्यकर्ताओं की रक्षा के लिये प्रशासनिक कदम उठाने की मांग की है।

17 जून 2009 को एक बयान जारी करते हुये बताया कि "यह समय प्रशासन को कुछ कार्य करने का है। लालगढ़ और राज्य के अन्य क्षेत्रों में माओवादियों, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस आदि जैसे सभी जो प्रतिशोध की राजनीतिक में लगे हुये है, लोकसभा चुनावों के परिणाम के बाद से फासीवादी आतंकवाद बढ़ा रहे हैं।"

वाम फ्रंट ने इस आतंक से राजनीतिक दबाव से निपटने की अपील की, यह भी कहा कि सरकार लालगढ़ में सरकार प्रशासनिक तरीके से निपटे। इसके अलावा जनता से अराजक तत्वों से सावधान रहने की अपील की गयी।

अन्य वक्तव्य में कहा कि "वाम मोर्चे ने लोकतंत्र की सच्ची भावना से जनादेश को स्वीकार कर लिया है। हम अपनी गलतियों को सुधारने का भरसक प्रयास करेंगे, लेकिन इस समय हमारा सारा ध्यान आतंकवाद ताकतों पर लगा हुआ है"।

हम इसी प्रकार की 1970 के फासीवादी आतंक की याद दिलाना चाहते हैं कि जब सीपीआई (एम) और अन्य वामदलों के 1200 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी गयी थी। जिसमें फारवर्ड ब्लॉक के अध्यक्ष और वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी साथी हेमन्ता कुमार बासु तथा सीपीआई (एम) के राज्य इकाई के सदस्य एवं वयोवृद्ध नेता साथी जिवन मायती की भी निर्मम हत्या कर दी गयी थी।

ऐतिहासिक 1977 के चुनाव में जनविरोधी सत्ताधारी कांग्रेस की पराजय को राज्य ने देखा है। वाममोर्चे की सत्तसीन के पश्चात्, राज्य में कहीं भी विपक्षी नेताओं पर हमल या मारपीट नहीं की गया, या उनके घरों में आग नहीं लगायी गयी, या उनकी पार्टी कार्यालयों को ध्वस्त या जलाया नहीं गया। यह केवल वाम मोर्चा ही जिसने विपक्ष के अधिकारों को समय-समय पर सम्मानित किया है। जनता ने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत सत्ता के

विरुद्ध वामविरोधी ताकतों को वोट देने के लिये एकत्रित हुये।

बड़ी दु:ख के साथ हमें यह जमा करा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना 2 मार्च 2009 के दिन ही विपक्षी गुटों ने हमारे 53 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी, जिसमें 2 फारवर्ड ब्लॉक के कार्यकर्ता थे तथा 51 सीपीआई(एम) के कार्यकर्ता थे। हमारे साथी हर रोज मारे जा रहे हैं। हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को बलर्पूक अपना घरबार छोड़ने के लिये मजबूर किया जा रहा है।

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में – जनता का नया परीक्षण

एस.पी. तिवारी, महासचिव टीयूसीसी

15वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम चौंकाने वाला रहा। संप्रग शासन काल में महँगाई की मार ने आम आदमी को त्रस्त कर दिया था, किसानों की आत्महत्या भी जारी थी। फिर भी अचानक परमाणु करार के मुद्दे पर सरकार को बाहर से समर्थन दे रही वामपंथी दलों द्वारा समर्थन वामपसी के बाद – सरकार (सपा के समर्थन से) तो बच गयी पर इस चोट ने कांग्रेस के नेताओं को और आक्रामक बना दिया। चुनावों का नतीजा एकतरफा हो गया, कांग्रेस के नेतृत्व में संप्रग की सरकार केन्द्र में 1988 के बाद सबसे बड़े बहुमत के साथ आ गयी पर इन चुनावों में जनता की राजनैतिक कारगुजारी का विलेषण करें तो पता चलता है कि–

1. इस चुनाव में करीब 300 से ज्यादा करोड़पति लोक सांसद बनकर देश पर शासन करने के लिये दिल्ली पहुँच गये।
2. कुल सांसदों का 90 प्रतिशत से ज्यादा महिलाओं को जनता ने जिताकर देश की संसद में उनका प्रतिनिधित्व आजादी के बाद सबसे ज्यादा बना दिया।
4. बड़े से बड़े बाहुबली सांसद, जिन्होंने अपने स्थान पर अपनी पत्नियों या रिश्तेदारों को चुनावों में उतारा था, ज्यादातर चुनाव हार गये।
5. जनता ने क्षेत्रीय दलों के स्थान पर राष्ट्रीय दलों की ओर झुकाव दिखाया।
6. विकास के लिये कार्यरत प्रांतीय सरकारों पर जनता ने अपना भरोसा जताया।
7. राजनैतिक चौसर पर काबिज सत्ता के सौदागरों को सत्ता से बेदखल कर दिया।

अब देखना है कि सत्ता की मोहिनि मादक बनकर कांग्रेस की पुरानी रंगदारी परंपरा से निकाल कर जनता की वांक्षित अपेक्षाओं पर खरी उतरती हैं या फिर से जनता को दुबारा नये सत्ताधारियों की नब्ज टटोटलना पड़ता है। यह आने वाला समय निर्धारित करेगा।

आस्ट्रेलिया में नस्लवाद की घुसपैठ

आस्ट्रेलिया में अध्ययन के लिये भारतीय छात्रों पर आस्ट्रेलिया के हताश और पथभ्रष्ट युवाओं द्वारा हिसंक हमला किया गया। वर्तमान आर्थिक मंदी और इसके प्रभाव का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है और सैकड़ों लोगों की नौकरी छूट रही है। इस बेरोजगार स्थिति ने युवाओं में अराजकता की स्थिति पैदा कर दी है। ये बेरोजगार नौजवान पूरी तरह से निराश हो गये है और अपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जा रहे हैं।

यह भी सत्य है कि आस्ट्रेलिया के नौजवानों का एक भाग यह सोचता है कि भारतीय छात्र हम आस्ट्रेलिया वालों से नौकरी छीन रहे हैं। लेकिन सत्य यह भी है कि भारतीय छात्रों का आस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में पिछले वर्ष 2 बिलियन का योगदान रहा है। शिक्षा आस्ट्रेलिया का तीसरा सबसे बड़ा विशेषज्ञ आर्थिक अर्जक है। एक लाख से ज्यादा भारतीय छात्र आस्ट्रेलिया में शिक्षा ग्रहण करते है। लगभग 4700 भारतीय छात्र तो सिर्फ मेलबोर्न में ही है।

भारतीय छात्रों ने मेलबोर्न सहित आस्ट्रेलिया के अन्य बड़े शहरों में फेडरेशन ऑफ इण्डियन स्टूडेन्ट्स इन आस्ट्रेलिया के बैनर तले एक विरोध रैली और धरना प्रदर्शन का आयोजन किया।

विदेशों में शिक्षा ग्रहण कर छात्रों की रक्षा के लिये भारत सरकार को और भी महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे, सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलेगा। भारत सरकार को अपने सभी राजनैतिक चैनलों को इस उद्देश्य में लगा देना चाहिये।